

अभिषेक मनु सिंघवी और जयराम रमेश ने सारे घोड़े खोल दिये गांधी परिवार के बचाव में

इन दोनों की दलील थी, कोई जुर्म नहीं हुआ, कोई पैसे का लेन-देन नहीं हुआ, किसी को कुछ भी भुगतान नहीं हुआ

-रेणु मि्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 अप्रैल। नैशनल हैरल्ड केस में कांग्रेस नेताओं, राहुल, सोनिया गांधी तथा अन्य के खिलाफ दाखिल चार्ज शीट को लेकर कांग्रेस और सत्तारूढ़ भाजपा टकराव की मुद्रा में आ गये हैं। कांग्रेस ने दिल्ली सहित, पूरे देश में विरोध-प्रदर्शन किये। दिल्ली में पार्टी नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने एआईसीसी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, लेकिन ई.डी. कार्यालय की ओर नहीं बढ़ पाये, क्योंकि उन्हें रोकने के लिये, वहाँ भारी पुलिस बल तैनात था।

कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी तथा जयराम रमेश ने गांधी परिवार के बचाव में पूरा जोर लगा दिया। उन्होंने कहा कि कोई अपराध नहीं हुआ, पैसे का कोई लेन-देन नहीं हुआ, किसी को कोई पैसा नहीं दिया गया तथा ए.जे.एल. एवं यंग इंडियन या अन्य

■ कांग्रेस ने दिल्ली में व देश के कई स्थानों पर प्रदर्शन आयोजित किये, नैशनल हैरल्ड के मामले में ई.डी. द्वारा राहुल गांधी व सोनिया गांधी के खिलाफ राउज़ एवेन्यु कोर्ट में चार्ज शीट दायर करने पर।

■ भाजपा का नेतृत्व अब यह आंक रहा है कि राहुल गांधी व सोनिया गांधी के खिलाफ कार्यवाही करने पर, जनता में क्या प्रतिक्रिया होगी।

■ सवाल यह उठ रहा है कि ऐसी क्या आवश्यकता थी यंग इंडिया का गठन करने की तथा पचास लाख रूपए देकर कंपनी की पुरानी सभी देनदारियाँ खरीदने की? और क्या, यह सब जोखिम उठाने के बाद, गांधी परिवार, नैशनल हैरल्ड की हजारों करोड़ रूपए की सम्पत्ति को कंट्रोल करने में सफल होगा?

किसी के भी बीच कोई वित्तीय लेन-देन नहीं हुआ।

हालांकि, कांग्रेस बार-बार यह कह रही है कि कोई गलत काम नहीं

हुआ, फिर भी, राउज़ एवेन्यु कोर्ट में चार्ज शीट पेश कर दी गई है तथा 25 अप्रैल को केस की सुनवाई होनी है। गांधी परिवार को जमानत के लिये

कोर्ट में अर्जी लगानी होगी तथा आरोप तय किये जायेंगे और ई.डी. ने कहा है कि वह अतिरिक्त चार्ज शीट और पेश करने वाली है।

राजनैतिक हलकों में दोष-सिद्धि (कनविक्शन) तथा गिरफ्तारी की चर्चाएं चल रही हैं। भाजपा नेतृत्व भी इस बात का आकलन कर रहा है कि राहुल और सोनिया गांधी के मुद्दे पर जनता की प्रतिक्रिया क्या होगी। प्रश्न यह भी पूछा जा रहा है कि आखिर यंग इंडियन बनाने की जरूरत क्या थी, और क्या कांग्रेस नेतृत्व ने 50 लाख रूपए दिये, 90 करोड़ रूपए का कर्ज खरीदा तथा ऐसा करके क्या कांग्रेस नेतृत्व अब इस स्थिति में है कि वह हजारों करोड़ की नैशनल हैरल्ड सम्पत्तियों को नियंत्रित कर सके।

एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर ई.डी. गांधी परिवार को दोषी सिद्ध करना चाहती है, तो उसे इसके साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।

जस्टिस गवई 14 मई को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने

नयी दिल्ली, 16 अप्रैल। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने शीर्ष अदालत के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी आर गवई को अपना उत्तराधिकारी नामित किया है। मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने न्यायमूर्ति गवई को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिखा है। यदि मंजूरी मिली तो न्यायमूर्ति गवई 14 मई, 2025 को मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने के बाद अपनी सेवानिवृत्ति

■ **वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उन्हें उत्तराधिकारी नामित किया।**

23 नवंबर, 2025 तक इस पद पर बने रह सकते हैं। न्यायमूर्ति खन्ना का मुख्य न्यायाधीश पद का कार्यकाल 13 मई, 2025 तक है।

इसके बाद वे सेवानिवृत्ति हो जाएंगे। न्यायमूर्ति गवई को 24 मई, 2019 को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। परंपरा के अनुसार, निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश अपनी सेवानिवृत्ति से एक महीने पहले सरकार को अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफािश भेजते हैं।

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को बीस साल की सजा

जयपुर, 16 अप्रैल। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 17.6 साल की नाबालिग के साथ समय-समय पर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रामस्वरूप को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने अभियुक्त पर 2.50 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी कैलाश चन्द्र अट्वासिया ने अपने आदेश में कहा कि यौन अपराध बच्चे के मन पर गहरा प्रभाव डालता है। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख अपनाने के बजाए उसे उचित दंड देना

■ **पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने अभियुक्त पर 2.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।**

जरूरी है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि पीड़िता ने 14 जनवरी, 2022 को कालांडेरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि 6 दिसंबर, 2021 को स्कूल जाते समय अभियुक्त उसे रास्ते से अपने साथ जबर्न हिंगोनिया ले गया और दुष्कर्म कर वापस छोड़ दिया। इसके बाद 11 जनवरी, 2022 को वह स्कूल से लौट रही थी तो अभियुक्त उसे रास्ते में मिला और साथ जाने के लिए मजबूर करने लगा। इस दौरान शोर सुनकर आसपास के लोग और उसके परिजन (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘ अन्नाद्रमुक चुनाव जीतने के बाद स्वयमेव सरकार बनायेगी, यह गठबंधन की सरकार नहीं होगी’

अन्नाद्रमुक नेता, पलानीस्वामी की इस घोषणा से भाजपा काफी स्तब्ध!

■ अभी तक भाजपा के स्थानीय नेता बड़े जोर-शोर से कह रहे थे कि एनडीए, जिसमें अन्नाद्रमुक भी शामिल है, तमिलनाडु में सरकार बनायेगा। पर, यह भी सच है कि अमित शाह ने अन्नाद्रमुक के एनडीए में शामिल होने के बाद यह जरूर कहा था कि अन्नाद्रमुक ने एनडीए में शामिल होते समय कोई शर्त नहीं रखी है।

■ पर, वक्त बोर्ड का संशोधित विधेयक संसद में पारित होने के बाद, शायद अन्नाद्रमुक ने यह कहा कि यदि अन्नाद्रमुक-भाजपा के साथ मिलजुल कर सरकार बनायेगी, तो उसे मुस्लिम वोटों का नुकसान होगा। अतः राजनीतिक मजबूरी के कारण, अन्नाद्रमुक को यह घोषणा करनी पड़ी कि उसका व भाजपा का साथ केवल चुनाव जीतने तक ही है, यह साथ सरकार बनाने के लिए नहीं है।

दरअसल, भाजपा के साथ हुये गठबंधन का अन्नाद्रमुक के अंदर जो विरोध हो रहा है, उससे पलानीस्वामी इस समय भारी तनाव में हैं।

अन्नाद्रमुक के नेता, अल्पसंख्यक समुदाय की प्रतिक्रिया के कारण भी परेशान हैं, क्योंकि भाजपा के साथ हुये गठबंधन के कारण अन्नाद्रमुक को अल्पसंख्यकों के वोट नहीं मिलेंगे।

बुधवार को जब विधानसभा में बोलने की अनुमति नहीं दिये जाने के विरोध में पलानीस्वामी ने वॉकआउट का नेतृत्व किया, उसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह गठबंधन तो केवल चुनावों के लिये है तथा अगले वर्ष होने वाले चुनावों में अगर गठबंधन की जीत होती है तो (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रधानमंत्री द्वारा कटरा-श्रीनगर वंदे भारत का “लांच” स्थगित हुआ

सरकार की ओर से आयोजन को आगे खिस्काने का अधिकृत कारण मौसम की खराबी बताया जा रहा है

-श्रीनंद झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 19 अप्रैल को प्रस्तावित कटरा-श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन स्थगित कर दिया गया है।

इस स्थगन के लिए आधिकारिक कारण खराब मौसम बताया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने आगामी दिनों में जम्मू-कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना जताते हुए यैलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं।

हालांकि, एक सवाल अब भी बना हुआ है: क्या यह स्थगन सुरक्षा कारणों से किया गया है?

अधिकारियों के अनुसार, हाल के दिनों में सुरक्षा बलों ने जम्मू के उधमपुर, कटुआ और पुंछ जिलों में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए हैं और “टारगेटेड स्ट्राइक्स” रोकने के

■ पर, यह आम चर्चा में है, कि स्थगित होने का असली कारण है, आतंकवादी गतिविधियों के कारण असुरक्षा का माहौल।

■ जैसा, कि विदित ही है, सिक्युरिटी एजेंसियां उधमपुर, कथुआ व पुंछ जिलों में हाई-अलर्ट की स्थिति में हैं।

■ सोमवार को ही सुरक्षा एजेंसियों ने भारी कॉर्डन ऑफ किया, सुरनकोट तहसील के लसाना गांव में आतंकवादियों के छुपे होने की खबर के बाद।

लिए हाई अलर्ट पर हैं।

स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, सोमवार को पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील के लस्साना गांव में आतंकी गतिविधियों की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया।

प्रस्तावित यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को विनाब रेल पुल और अंजी खड्ड रेल पुल का दौरा करना

था, जिसके लिए दो हेलीपैड तैयार किए गए थे।

प्रधानमंत्री को श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से श्रीनगर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस के एक विशेष कश्मीर संस्करण को हरी झंडी दिखायी थी। कटरा-श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन में अनेक विशेषताएं होंगी, जैसे हीटिंग सिस्टम और ट्रेन इंजन की विंडस्क्रीन पर एंडी-फॉग सुविधा। इस नई ट्रेन का

ट्रायल भारतीय रेल द्वारा 23 जनवरी को किया गया था।

अधिकारियों ने कहा कि उद्घाटन के लिए नई तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं, लेकिन संभावना है कि यह अप्रैल के अंत तक किया जाएगा।

कश्मीर लाइन, जिसे उधमपुर-श्रीनगर-बaramulla रेल लाइन के नाम से जाना जाता है, 272 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 119 किलोमीटर सुरंगें शामिल हैं।

इस परियोजना में विश्व का सबसे ऊँचा रेल पुल, विनाब ब्रिज और भारत का पहला केबल-स्टेड रेल पुल, अंजी खड्ड ब्रिज शामिल हैं।

पहली बार ट्रेन में एटीएम लगा

नई दिल्ली, 16 अप्रैल। ट्रेन में सफर करते वक्त अगर नकदी पास न हो तो हर कोई चिंतित हो जाता है। लेकिन, अब इस चिंता से रेलवे मुक्ति दिलाने जा रहा है। भारतीय रेलवे ने एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए मुंबई-मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस को देश की पहली ऐसी ट्रेन बना दिया है, जिसमें एटीएम लगा हुआ है। ट्रेन के एसी कोच में लगे इस एटीएम से चलती ट्रेन में ही यात्री कैश निकाल सकते हैं। इस एटीएम

■ यदि अच्छा रिस्रॉन्स मिला तो लम्बी दूरी की अन्य ट्रेनों में भी एटीएम लगाये जायेंगे।

को खास तरह से डिजाइन किया गया है, ताकि यह ट्रेन के पूरी रफ्तार में होने के बावजूद भी ठीक से काम कर सके। साथ ही इसे चोरों से बचाने के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं और इस पर चौबीस घंटे सीसीटीवी से निगरानी भी रखी जाएगी। रेलवे का कहना है कि अगर मुंबई-मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में लगे एटीएम को अच्छा रिस्रॉन्स मिलता है तो फिर लंबी दूरी की अन्य ट्रेनों में भी एटीएम लगाए जाएंगे।

यह नई सुविधा भुसावल रेलवे डिवाजन और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की साझेदारी में शुरू की गई है और इसका ट्रायल रन भी सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है।

एकल पट्टा प्रकरण में रिक्विज़न याचिका वापस लेने पर बहस पूरी हुई

जयपुर, 16 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट में बुधवार को पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और अन्य अफसरों से जुड़े एकल पट्टा प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से पूर्व में पेश रिवीजन याचिका को वापस लेने के प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों

■ **अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने हाई कोर्ट में कहा कि मौजूदा राज्य सरकार आरोपियों के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर केस आगे बढ़ाना चाहती है।**

की बहस पूरी हो गई है। चीफ जस्टिस एमएएम श्रीवास्तव ने प्रार्थना पत्र पर अपना फैसला बाद में देना तय किया है। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-सुकुमार साह-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 अप्रैल। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापारिक गतिरोध के बीच, सुपर लग्जरी गुड्स मार्केट में एक नया मोर्चा चुपचाप खुल गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप अमेरिकी फर्मी पर उत्पादन को वापस अमेरिका में लाने का दबाव बना रहे हैं और साथ ही चीनी आयात पर भारी शुल्क लगा रहे हैं। ऐसे में चीन के सप्लायरों ने पलटवार करने के लिए सोशल मीडिया को चुना है। ये लोग सार्वजनिक रूप से यह खुलासा कर रहे हैं कि कैसे वे दुनिया के कुछ सबसे प्रतिष्ठित ब्रांडों के लिए लग्जरी गुड्स

■ बरकिन, लुई विटों, शनैल, एस्टी लॉडर व बॉबी ब्राउन जैसे लग्जरी ब्रांड के बैग अमेरिका में रिटेल में 29-30 लाख रुपये में बिकते हैं।

■ पर, अधिकतर ये आइटम चीन में ही बनते हैं तथा इनकी कुल लागत 1.2 लाख रूपए ही आती है।

■ चीन के व्यापारी अब ये आइटम, बिना “ब्रॉण्ड टैग” के 1.2 लाख रुपये में सीधे ग्राहक को बेच रहे हैं। ये व्यापारी ग्राहक को यह भी समझाते जा रहे हैं कि इन आइटम्स में लगे माल की कीमत क्या है तथा चीन के कारीगरों के हुनर की कीमत को भी जोड़ दिया जाये तो भी बनाने का खर्च बिक्री के दाम का दसवां हिस्सा ही होगा।

■ बाकी सारा पैसा अमेरिका के व्यापारियों का मार्क-अप व विज्ञापन खर्च हैं।

■ इस रणनीति से ग्राहक के मन में लग्जरी आइटम की घनघोर मुनाफा गिरी तो सामने आयी ही, साथ ही चीन के कारीगरों के हुनर व मेहनत का जायका भी देखने को मिला ग्राहक को। इससे, चीन का माल घटिया होने की छवि भी अपने आप खत्म होने लगी है।

बनाते हैं और उन्हीं उत्पादों को अब सीधे

उपभोक्ताओं को उनकी खुदरा कीमतों

से बहुत ही कम कीमत में बेच रहे हैं।

एक डिजिटल आक्रमण, जो गति

संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी परियोजना को दो वर्षों में पूरा करें : भजनलाल शर्मा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी (रामजल सेतु लिंक) परियोजना प्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजना है। जिसके माध्यम से प्रदेश के 17 जिलों में पेयजल

के कार्यदिशे जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि इन पैकेज में भूमि अवाप्ति के अवार्ड, वन क्लीयरेंस एवं अन्य क्लीयरेंस के कार्य में गति लाई जाए। उन्होंने इस परियोजना में अब तक

- यमुना जल समझौते की बैठक 20 अप्रैल को, पिलानी में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी टास्क फोर्स की बैठक
- भूमि अवाप्ति के कार्यों में समन्वय के लिए विशेषाधिकारियों की होगी नियुक्ति
- ईसरदा पेयजल परियोजना को जून तक किया जाए पूरा



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को उनके निवास पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी सहित विभाग के उच्चाधिकारी मौजूद रहे।

एवं सिंचाई के साथ ही इन जिलों में स्थापित होने वाले उद्योगों को भी आवश्यकता के अनुरूप पानी मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि आगामी दो वर्षों में इस परियोजना को पूरा करने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड पर कार्य किया जाए। राज्य सरकार इसके लिए संबंधित विभाग को मानव संसाधन, नियमों में सरलीकरण सहित अन्य सभी सहायताएं उपलब्ध कराएगी। शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित जल संसाधन विभाग, इंंदिरा गांधी नहर विभाग, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि इस परियोजना की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक 15 दिन में मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए एवं भूमि अवाप्ति के कार्यों में समन्वय के लिए विशेष रूप से अधिकारियों को नियुक्त किया जाए।

मुख्यमंत्री ने संशोधित पीकेसी ईआरसीपी परियोजना के पैकेज 1, 2 एवं 3 के अंतर्गत विवरण एवं प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि परियोजना को त्वरित गति प्रदान करने के लिए प्रथम चरण में 9,600 करोड़ रुपये के कार्यों

हो चुकी अधिगृहीत भूमि पर कार्य प्रारंभ करने का सुझाव दिया। साथ ही, उन्होंने भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले लोगों के पुनर्वास की समुचित व्यवस्था के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना जल समझौते के प्रथम चरण में ताजेवाला हैड से प्रदेश में जल लाने के लिए प्रवाह प्रणाली हेतु संयुक्त डीपीआर बनाने पर सहमति बनी है। इसी क्रम में डीपीआर के लिए गठित संयुक्त टास्क फोर्स की पहली बैठक 7 अप्रैल को यमुनानगर में हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यमुना जल समझौते की डीपीआर को लेकर संयुक्त टास्क फोर्स की दूसरी बैठक 20 अप्रैल को पिलानी में होगी। उन्होंने अधिकारियों को नक्शे एवं अलाइमेंट की डिजाइन की तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। शर्मा ने कहा कि परवन वृहद् बहु-उद्देशीय सिंचाई परियोजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि परियोजना में बांध निर्माण कार्य एवं पाइपलाइन वितरण प्रणाली से लेकर डिग्री एवं पंप हाउस कार्यों में गति लाई जाए। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

गर्मी के मौसम में पेयजल आपूर्ति निर्बाध हो : भजनलाल शर्मा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गर्मी के मौसम में पेयजल प्रबंधन एवं समर कंटी-जैसी प्लान को लेकर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्ययोजना के तहत आमजन को निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जिला कलक्टरों की अनुशंसा पर जिलों में पेयजल से संबंधित आकस्मिक कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पीएचईडी अधिकारियों को फील्ड में रहकर जलापूर्ति की व्यवस्था के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पेयजल से संबंधित योजनाओं के लिए ग्राम स्तर पर दो जल मित्र बनाए जाएं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनका सहयोग लिया जा सके।

- ‘फील्ड में रहें अधिकारी, जलापूर्ति व्यवस्था रखें सुचारू’

को सुचारू बनाए रखने के लिए नवीन नलकूप एवं हैण्डपंप लगाए जाएं। उन्होंने पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यकता के अनुसार टैंकों के जरिए पेयजल परिवहन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पेयजल से संबंधित योजनाओं के लिए ग्राम स्तर पर दो जल मित्र बनाए जाएं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनका सहयोग लिया जा सके। इस अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी सहित विभाग के उच्चाधिकारी मौजूद रहे।

कम वसूली वाले प्राथमिक भूमि विकास बैंकों को नोटिस दें : मंजू राजपाल

जयपुर। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल ने कहा कि सहकारी भूमि विकास बैंकों के ऋणों हेतु लाई जा रही मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 का लाभ सभी पात्र लोगों को मिलना

- ‘मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना का करें व्यापक प्रचार-प्रसार’



सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल ने बुधवार को नेहरू सहकार भवन में समीक्षा बैठक को सम्बोधित किया।

लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि योजना को क्रियान्वित करने के लिए तैयार किए जा रहे पोर्टल को पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए। जिन जिलों में अधिक ऋण राशि बकाया है, उनमें अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए अलग रणनीति बनाई जाए।

बैठक में भूमि विकास बैंक के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि योजना की क्रियान्विति के लिए पोर्टल लगभग तैयार किया जा चुका है और कुछ ही दिनों में इसकी टेस्टिंग हो जाएगी। पोर्टल पर ऋणियों की सहूलियत के लिए विभिन्न

सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक सप्ताह पात्र ऋणियों को मैसजेज के माध्यम से सूचना दी जाएगी। साथ ही, कॉल सेंटर की स्थापना कर सभी पात्र व्यक्तियों को कॉल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों में प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। जिन जिलों में अधिक डिमांड है, वहां वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के प्रबंध निदेशक जितेंद्र प्रसाद ने बताया कि ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत

नियमित खातों में कुल 111.98 करोड़ रुपये की वसूली की गई है, जो लक्ष्य का 91.04 प्रतिशत है। वहीं, प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के स्तर पर वर्ष 2024-25 के दौरान लगभग 80 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है। उन्होंने कहा कि ब्याज अनुदान योजनाओं के अंतर्गत अवधिपार ऋणों के मामलों में समझाइश एवं सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से वसूली कार्यक्रम जारी रखा जाएगा। बैठक में राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

गिव अप अभियान में अब तक 17.52 लाख अपात्रों ने छोड़ी खाद्य सुरक्षा : गोदारा

जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में जयपुर जिले में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय अधिकारियों द्वारा जिले में गिव अप अभियान के तहत अपात्रों द्वारा खाद्य

- ‘खाद्य सुरक्षा पोर्टल पुनः प्रारंभ होने से जुड़े 19.70 लाख नए लाभार्थी’
- अभियान के माध्यम से अपात्रों द्वारा एनएफएसए से नाम हटाने के कारण प्रदेश सरकार को 324 करोड़ रुपए के राजस्व की बचत प्रतिवर्ष होगी

सब्सिडी छोड़ने, खाद्य सुरक्षा पोर्टल के पुनः प्रारंभ होने के उपरांत नए लाभार्थियों के जोड़ने एवं खाद्य सुरक्षा सूची से जुड़ने हेतु लंबित आवेदनों की स्थिति पर विस्तार से प्रस्तुतिकरण दिया गया। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि बढ़ाई जाने से प्रदेश के करोड़ों खाद्य सब्सिडी धारकों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार र्विचतों के लोगो ने स्वतः खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाया है। इस अभियान के माध्यम से अपात्रों द्वारा एनएफएसए से नाम हटाने के कारण प्रदेश सरकार को 324 करोड़ रुपए के राजस्व की बचत प्रतिवर्ष होगी। साथ ही संपन्न व्यक्तियों द्वारा खाद्य

अधिक से अधिक जागरूकता फैलाई ताकि वे समुचित लाभ ले सकें। आमजन एवं जनप्रतिनिधियों से हर स्तर पर उचित समन्वय स्थापित कर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है की अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। गोदारा ने कहा कि सक्षम लोगों को खाद्य सब्सिडी छोड़ने हेतु प्रेरित करने के लिए गत वर्ष शुरू किए गए गिव अप अभियान के तहत आज तक 17.52 लाख अपात्र लोगों ने स्वतः खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाया है। इस अभियान के माध्यम से अपात्रों द्वारा एनएफएसए से नाम हटाने के कारण प्रदेश सरकार को 324 करोड़ रुपए के राजस्व की बचत प्रतिवर्ष होगी। साथ ही संपन्न व्यक्तियों द्वारा खाद्य

सब्सिडी छोड़ने से बचे हुए अन्न का र्विचत पात्रों को खाद्य सुरक्षा देने में इस्तेमाल किया जा सकेगा। गोदारा ने कहा कि एनएफएसए से नाम हटवाने वाले संपन्न व्यक्ति मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना का लाभ भी नहीं ले सकेंगे। इससे राज्य सरकार को होने वाली बचत का भी उपयोग वास्तविक हकदारों के कल्याण हेतु किया जा सकेगा। उन्होंने कहा की स्वतः खाद्य सब्सिडी नहीं छोड़ने वाले सक्षम लाभार्थियों के विरुद्ध आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई की जाए। राशन वितरण को अनियमितता बरतने वाले राशन डीलरों पर भी विभागीय अधिकारी उचित कार्रवाई करें। बैठक में जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह ने कहा कि संपन्न व्यक्तियों का कर्तव्य है की वह गरीबों के हक में खाद्य सब्सिडी

छोड़ें। उन्होंने कहा की सक्षम लोगों द्वारा छोड़ी गई सब्सिडी गरीब के मुंह का निवाला बनती है। खाद्य सुरक्षा सूची से जुड़े सभी संपन्न व्यक्तियों को गिव अप अभियान में भाग लेकर इस पुनीत कार्य में पूर्ण सहभागिता निभानी चाहिए।

बैठक में हवा महल विधायक बालमुकुंदाचार्य, आदर्श नगर विधायक रफीक खान, चौमू विधायक शिखा मिल बराला, उपेन यादव, चंद्र मोहन मीणा, सांगानेर प्रधान भंवर कंवर, नगर पालिका चौमू अध्यक्ष विष्णु सैनी, रामपुरा डाबडी प्रधान हरदेव यादव, शाहपुर प्रधान मंजू शर्मा, मनोहरपुर नगर पालिका अध्यक्ष सुनीता प्रजापत, शाहपुरा नगरपालिका चेयरमैन बंशीधर सैनी सहित विभिन्न प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उन्होंने विभागीय योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार, जिला कलेक्टर जयपुर जितेंद्र कुमार सोनी, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पुनम सागर सहित सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

कांग्रेस ने ई.डी. ऑफिस के बाहर धरना दिया

जयपुर। नेशनल हेराल्ड मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की ओर से पेश चार्जशीट को लेकर कांग्रेस की ओर से देशभर में प्रदर्शन किया गया। इसी सिलसिले में जयपुर में ज्योति नगर स्थित ईडी कार्यालय के बाहर धरना देते हुए कांग्रेस नेताओं ने इस कार्रवाई के विरोध में आगे भी सड़कों पर उतरने के लिए कार्यकर्ताओं का आह्वान किया।

धरने में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटारसा, टीकाराम जूली सहित कई विधायक और पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटारसा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर कहा कि हमारी सरकार ने गांधीवादी तरीके से सरकार चलाई। हम भी ऐसे ही कार्रवाई करते तो भाजपा के कई नेता जेल में होते। उन्होंने कहा कि मदन दिलावर पर 14 मुकदमे दर्ज हैं, उनका काम केवल अंगरेज बयानबाजी करना ही है और उसे शिखा जैसा पवित्र महकमा दिया गया है। हमारी सरकार में ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई होती तो वो जेल में होते। इनकी बोलने की हिम्मत नहीं होती।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मोदी सरकार जॉच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। इन एजेंसियों में काम

- राहुल-सोनिया के खिलाफ चार्ज शीट का विरोध

नेशनल हेराल्ड की संपत्ति खुर्द बुर्द कर देना गांधी परिवार मॉडल ऑफ डेवलपमेंट : मदन राठौड़

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के देशभर में धरने और प्रदर्शन करने की घोषणा पर कहा कि धरना प्रदर्शन उनका अधिकार है पर उन्हें जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है। राठौड़ ने नेशनल हेराल्ड मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 1937 में नेशनल हेराल्ड शुरू हुआ था उस समय 5000 शेयर होल्डर थे, यह संपत्ति स्वतंत्रता सेनानियों की है किसी खासदानी की जागीर नहीं है। यह कंपनी जब बन रही थी तब सरदार पटेल ने इसके लिए हो रहे धन संग्रह पर सवाल उठाया था कि जिस तरह से लोगों में पैसा लिया जा रहा है यह ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नागुता ने भी इसके लिए धन इकट्ठा किया था पर जो स्वतंत्रता सेनानियों की प्रॉपर्टी थी वह अब खानदान की प्रॉपर्टी बना दी गई।

राठौड़ ने कहा कि 2008 में नेशनल हेराल्ड का पब्लिकेशन बंद हो गया, कांग्रेस ने उसे 90 करोड़ रुपए दिए। एक राजनीतिक दल

- ‘50 लाख में हजारों करोड़ की संपत्ति पर कब्जा, 76 फीसदी मां-बेटे की भागीदारी’
- ‘भूल केवल वोट बैंक के लिए के दंगाईयों का साथ दे रही है ममता बेनर्जी’

किसी प्राइवेट बॉडी को लोन नहीं दे सकती, यह नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। जब नेशनल हेराल्ड की कंपनी एसोसिएट जनरल लोन नहीं चुका पाई तो कॉर्पोरेट षड्यंत्र करने का षांघी परिवार के पास संपत्ति आ जाए इसके लिए यंग इंडिया नाम से एक कंपनी बनाई गई। उन्होंने कहा कि इस कंपनी में 38 फीसदी शेयर सोनिया गांधी के और 38 फीसदी शेयर राहुल गांधी के पास रखे गए। शेष शेयर मोतीलाल बोहरा और ऑस्कर फर्नांडीज जैसे लोगों के पास थे। इस कंपनी पर ट्रॉसफर किए गए केवल 50 लाख रुपए हैं। जिस कंपनी को यह शेयर दिए गए उस कंपनी में 76 फीसदी की भागीदारी माता और पुत्र की थी, जिसकी दिल्ली, मुंबई,

लखनऊ, भोपाल में हजारों करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी। वह भी इस यंग इंडिया के नाम पर ट्रॉसफर हो गई और 90 करोड़ रुपए जो कांग्रेस ने दिए वह राइट ऑफ कर दिए गए। यह एक बड़ा षड्यंत्र था हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को हड़पने का। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ईडी ने मोतीलाल बोरा, पवन बंसल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सबसे बुलाकर पूछा पर किसी के पास भी जवाब नहीं था। 50 लाख रुपए में 90 करोड़ का राइट ऑफ हो जाना और करोड़ों की संपत्ति एक अनजानी सी अनाम सी कंपनी के हाथ चले जाना यह गांधी परिवार मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है। नेशनल हेराल्ड को सरकार द्वारा संपत्ति दी गई थी उसे खुर्द बुर्द करने का यह ष्टाचार का खुला आचरण है।

बजट घोषणाओं का शीघ्र समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें : दिलावर



पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने बुधवार को पंचायती राज भवन स्थित सभागार में विभाग की समीक्षा बैठक में भाग लिया।

जयपुर। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने वर्ष 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 की विभागीय बजट घोषणाओं के कार्यों का शीघ्र समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बजट घोषणाओं के कार्य में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त की और अधिकारियों को समय से घोषणाओं को पूरा करने के लिए निर्देशित किया।

दिलावर आज बुधवार को पंचायती राज भवन स्थित सभागार में विभाग की वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं के लम्बित प्रकरणों, कार्यों के क्रियान्वयन एवं अधिकारियों के रात्रि विश्राम के संबंध में

आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में कार्यों को पूर्ण करने के लिए समय सीमा निर्धारित करते हुए कार्यवाही प्रारम्भ करें। उन्होंने स्वामित्व योजना की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की गई बजट घोषणाओं के लंबित प्रकरणों के त्वरित क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों द्वारा किए गए दौरो और रात्रि विश्राम की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायतों में गंदगी पाए

डॉ. गर्ग ने पानी की समस्या का निदान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए

मंत्री ने लोगों से मुलाकात कर क्षेत्र के विकास एवं समस्याओं पर चर्चा की

भरतपुर 16 अप्रैल। पूर्व मंत्री व जूनून विधायक डॉ. सुभाष गर्ग ने जूनून के दौरे के दौरान शहर के पर्यटन नगर और विजय नगर कॉलोनी में पानी की समस्या की शिकायत के लिए स्थानीय लोगों की पानी की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने अन्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से मुलाकात कर क्षेत्र के विकास एवं समस्याओं पर चर्चा की।

विधायक डॉ. गर्ग ने जूनून के तीसरे दिन मंहगाया, नौह, नगला गोपाल, नौगाया, हथैनी, इकरन, नगला परशुराम, जाट मंडौली सहित शहरी क्षेत्र के विजय नगर, सारं नगर, सारस सहित अन्य क्षेत्रों में प्रवेश द्वारों की यात्रा की। साथ ही वे



पूर्व मंत्री व जूनून विधायक डॉ. सुभाष गर्ग ने क्षेत्र का दौरा कर लोगों के दुख दर्द जाने।

लोगों के दुख-दर्द भी शामिल हैं।

इंटरव्यू नगर और विजय नगर

कॉलोनी के लोगों ने पानी की समस्या

■ **गर्मी के मौसम को देखते हुए पानी की समस्या से संबंधित क्षेत्र में टचयूबेल लगाने के लिए निर्देशित किया।**

अधिकारियों को एमओयू पर क्रिएटर की पोस्ट के बारे में जानकारी ली और गर्मी के मौसम को देखते हुए नोएडा पानी की समस्या से संबंधित क्षेत्र में टचयूबेल पत्रिका के लिए निर्देशित किया। इसके अलावा डॉ. गर्ग ने विभिन्न वास्तुशिल्प कार्यक्रमों में नव दंपतियों और उनके भव्य कोमों को स्थापित किया।

जैन संतों पर हमला, कठोर कार्यवाही करने की मांग

हमले की घटना से सम्पूर्ण भारत वर्ष के जैन संतों में एवं जैन

धर्मावलंबियों में भारी आक्रोश है

भीलवाड़ा। मध्यप्रदेश मे जैन संतों पर हुए हमले व हमलावरों द्वारा संतों के साथ अमानवीय कृत्य करने के विरोध में जैन समाज के सदस्यों जैन कॉंफ्रेंस राजस्थान के अध्यक्ष आनंद चपलोट के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के नाम जापन सौंपकर अपराधियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही करने की माँग की। जापन मे बताया की मध्यप्रदेश के सिंगोली के पास कछाला बस स्ट्रेण्ड के आगे हनुमान मन्दिर पर जैन संत बलभद्र मुनि, शैलेश मुनि, मुनीन्द्र मुनि रात्रि

जेईई-मेन एआईआर-1 परीक्षा नौ पारियों में संपन्न हुई

कोटा, (निसं)। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई-मेन (बीई-बीटेक) जो कि इस वर्ष 22 से 29 जनवरी के मध्य 10 तथा अप्रैल माह में 2 से 8 अप्रैल के मध्य 9 पारियों में संपन्न हुई। दोनों पारियों में मिलाकर इस वर्ष इतिहास में सर्वाधिक 15 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने जेईई-मेन परीक्षा दी, परीक्षा का परीगम ऑल इंडिया रैंक के साथ 17 अप्रैल को जारी किया जाना संभावित हैं। एलन कॅरियर इस्टीमेट्यूट के कॅरियर काउंसिलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि इस वर्ष जेईई-मेन के जारी किए गए परीगमों में आल इंडिया रैंक-1 पर कई

स्टूडेंट्स आना तय है। इसका कारण जेईई-मेन द्वारा दो विद्यार्थियों के समान टोटल एनटीए स्कोर पर टाई लगने का मैथ्ड्स है। एनटीए द्वारा जारी की गई सूचना के अनुसार दो विद्यार्थियों के टोटल एनटीए स्कोर पर टाई लगने पर सर्वप्रथम मैथैमेटिक्स का एनटीए स्कोर, इसमें टाई होने पर फिजिक्स, इसके बाद कैमेस्ट्री के एनटीए स्कोर के आधार पर रैंक को प्राथमिकता दी जाएगी। उपरोक्त सभी विषयों में टाई लगने की स्थिति में विद्यार्थियों के कुल सही एवं गलत जवाबों के प्रातांकों के अनुपात को देखा जाएगा। इस स्थिति के बाद क्रमशः मैथैमेटिक्स, फिजिक्स एवं

कैमेस्ट्री के सही एवं गलत उत्तरों के नम्बर के अनुपात को देखा जाएगा। उपरोक्त सभी स्थितियों में टाई लगने पर विद्यार्थियों की एक समान आल इंडिया रैंक जारी कर दी जाएगी। ऐसी स्थिति में जिन विद्यार्थियों का परफेक्ट स्कोर 300 में से 300 है, उनकी एआईआर-1 जारी होगी।

ऐसे जारी होगी ऑल इंडिया रैंक:- अमित आहूजा ने बताया कि जेईई-मेन के अप्रैल सेशन के जारी किए गए परीगमों में विद्यार्थियों की ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी रैंक के साथ-साथ एडवांस परीक्षा देने की पात्रता भी जारी की जाएगी। ऑल इंडिया रैंक करने के लिए

विद्यार्थियों के जनवरी एवं अप्रैल सेशन के हांथर एनटीए स्कोर को लिया जाएगा। 7 डेसीमल में हाथर एनटीए स्कोर के आधार पर ही ऑल इंडिया रैंक जारी की जाएगी। ऑल इंडिया रैंक के साथ-साथ विद्यार्थी जिस कैटेगरी से संबंधित है, उसकी कैटेगरी रैंक जारी होगी। विद्यार्थी के जनवरी एवं अप्रैल के 7 डेसीमल में हाथर एनटीए स्कोर के आधार पर एडवांस्ड देने की पात्रता जारी की जाएगी। एडवांस्ड देने की पात्रता कैटेगरी के आधार पर अलग-अलग होगी। जेईई-मेन के आधार पर शीर्ष चुने हुए करीब ढाई लाख विद्यार्थी ही एडवांस्ड देने के पात्रता होंगे।

फैक्ट्री में लगी आग

टोंका। कोतवाली क्षेत्र स्थित निजाम बीडी फैक्ट्री के वर्कशॉप में बुधवार को अचानक आग लग गई, जिससे वर्कशॉप में रखी बीड़ी के बंडल (पैकेट) जलने लगे तथा धुंआ खिड़कियों आदि से निकल लगा तो अफरा-तफरी मच गई। घटना स्थल पर मौजूद लोगो ने पुलिस और दमकल को सूचना दी।

अगले तीन दिन तक पारा बढ़ने की चेतावनी

बीकानेर। अगले तीन दिन तक गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम शुष्क रहने की चेतावनी देते हुए मौसम विभाग ने बीकानेर में पारा 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका जताई है। कुछ स्थानो 'पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस भी जा सकता है। बीकानेर सहित पश्चिमी राजस्थान में तापमान में फिलहाल 19 अप्रैल तक कोई खास राहत की उम्मीद नहीं की जा रही है। नसिर्फ दिन में बल्कि रात में भी ठंडी हवाओं के लिए लोगो को एसी और कुलर का ही सहारा लेना पड़ेगा। रात का तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है।

बीकानेर में बीते चौबीस घंटे में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा है। दोपहर दो बजे के आसपास पारा उच्चतम स्कोर पर पहुंचे रहा है, वहीं शाम होते-होते कुछ राहत मिलती है। तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला अगले कुछ दिन तक जारी रहेगा।

बीकानेर में फिलहाल किसी तरह का पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नहीं है। ऐसे में तापमान भी कम नहीं होगा। सोमवार की रात राज्य में सबसे गर्म बीकानेर में रही। जब पारा 28.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था।

टायर रिट्रेडिंग फैक्ट्री में भीषण आग, क्षेत्र में दहशत



शहर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र की आजाद नगर कॉलोनी में स्थित कुम्भा सर्किल के निकट बस्ती में लगी आग।

एक ही रात में चोरों ने आधा दर्जन दुकानों के ताले तोड़कर लाखों की नकदी पर किया हाथ साफ

कृषि उपज मंडी समिति तथा सब्जी मंडी में संचालित दुकानों के तोड़े ताले

■ **सीसीटीवी कैमरे में कैद नकाबपोश चोर।**

खड़े कर दिए हैं। व्यापारियों में भय का माहौल है और उन्होंने मंडी में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। लगातार हो रही चोरियों से मंडी व्यवसायियों में आक्रोश है। जानकारी के अनुसार सब्जी मंडी में मंगलचंद मोतीराम फर्म के मालिक मोतीराम ने बताया कि चोरो ने उसकी दुकान के ताले तोड़कर 37 हजार आठ सौ रूपए चुरा ले गए। भागीरथमल मोहनलाल फर्म के राकेश सैनी ने बताया कि चोरो ने उसकी दुकान से 7 हजार, बालाजी फ्रूट सब्जी

मर्चेट के व्यापारी खेमराज सैनी ने बताया कि चोरो ने उसकी दुकान का ताला तोड़कर 30 हजार रूपए, श्री श्याम फ्रूट कंपनी के व्यापारी सुनील ने बताया कि उसकी दुकान का ताला तोड़कर 17 हजार रूपए और व्यापारी गिरधारीलाल ने बताया कि चोरो ने उसकी दुकान में रखे गल्ले से 15 हजार रूपए चुरा लिए।

वहीं कृषि उपज मंडी समिति में स्थित अनाज व्यापारी बनवारी लाल चौधरी की दुकान से चोर करीब 40 हजार रूपए की नकदी चोरी कर ले गए। इधर चोरी की सूचना के बाद मौकै पर एएसआई मालाराम, कांस्टेबल राजवीर सिंह पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया।

बीकानेर में कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर महिला से दुष्कर्म

■ **पीड़ित महिला ने कोर्ट से इस्त्ताफे के आधार पर गंगाशहर थाने में तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है।**

बीकानेर। कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर एक महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़ित महिला ने कोर्ट से इस्त्ताफे के आधार पर गंगाशहर थाने में तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है।

पुलिस के अनुसार पीड़िता के परिवार को मकान निर्माण के लिये रुपये की जरूरत थी। महिला अपने ही समाज के अचलाराम सांसी निवासी बायतु, बिंजाराम सांसी और उसके भाई ताजाराम सांसी से मिली।

आरोप है कि रुपए देने का झांसा देकर उन्होंने महिला को जोधपुर बुलाया। वहां से उसे अहमदाबाद ले गए। जहां कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर पिला दिया। उसके बाद महिला के साथ दुष्कर्म

किया। इसके बाद उसे बालोतरा में बंधक बनाकर दुष्कर्म किया।

पुलिस के अनुसार यह घटना पिछले साल 27 दिसम्बर से 31 दिसंबर के बीच की बताई जाती है। गंगाशहर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गफलत में मरीज के अटेंडेंट को ओ.टी. में ले जाकर लगा चीरा, मचा हड़कंप

घटनाक्रम के बाद अस्पताल प्रबंधन में

हड़कंप मचा हुआ है

■ **तीन सदस्य जांच कमेटी भी गठित कर दी गई है**

इसके बाद स्टॉफ उसे अंदर ले गया और ऑपरेशन थिएटर पर टेबल पर लेटा दिया।

उसके हाथ में फिस्टुला बनाने के लिए चीरा भी लगा दिया गया। इसी दौरान उसके बेटे का इलाज कर रहे डॉक्टर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि यह तो उनके मरीज का अटेंडेंट है। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ और हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद इस मरीज के वापस टांके लगाए गए। उसे ओटी से वापस उसके बेटे के बाई में भेज दिया। बाद में जिस मरीज का डायलिसिस फिस्टुला बना था उसका फिस्टुला बनाया गया।

जिस अटेंडर के साथ यह घटना हुई है वह पैरालाइड्ड है। वह ठीक से बोल नहीं पाता है। इसीलिए जब उससे पूछा गया तो वह कुछ भी नहीं बोल

पाया और डॉक्टर ने भी प्रोसीजर शुरू कर दिया। दूसरी तरफ ऑपरेशन थिएटर में भी प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है। ओटी में मरीज को ले जाने के पहले उसे ओटी की ड्रेस पहनाई जाती है लेकिन इस मरीज ने ड्रेस भी नहीं पहनी हुई थी। दूसरी तरफ हाथ में डायलिसिस फिस्टुला बनाने के लिए बाल हटाए जाते हैं और सफाई की जाती है वह भी नहीं हुई थी। इसके बावजूद भी ध्यान नहीं दिया। यह काफी छोटा प्रोसीजर था इसलिए डॉक्टर ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। मामले को लेकर सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक के कार्यवाहक अधीक्षक डॉ. विकास खंडेलिया का कहना है कि मरीज को जलाह दूसरे मरीज के अटेंडेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के संबंध को सूचना मिली है। कई तरीके की जांचकारियों सामने आ रही हैं। जांच के लिए तीन सदस्यों की कमेटी गठित कर दी है। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

4.24 लाख टन बजरी का अवैध खनन

बीकानेर। यहां अवैध खनन की सूचना पर जिला कलेक्टर की ओर से गठित एएसआईटी. दल ने ग्राम झ़झू के पास बजरी का अवैध खनन पकड़कर 19.11 करोड़ रुपए की पेनल्टी तय की है। एसआईटी मौके पर पहुंची तो दो अलग पीटो में अवैध खनन किया जा रहा था। टीम को देख कर मौके से अवैध खनन करने वाले लोग भाग निकले। मौके पर देखने पर दो एक्सकैवेटर मशीनें एवं तीन डंपरों को जब्त किया गया ।

मौके पर कार्यवाही हेतु हल्का पटवारी झ़झू को बुलवाया गया। दोनों अवैध खनन के पीट वाली भूमि के खातेदार उदाराम, कोजाराम, मानाराम मेघवाल, पप्पूराम सांसी, पाबूराम नायक हैं ।

मौके पर देखने पर दो एक्सकैवेटर मशीनें एवं तीन डंपरों को जब्त किया गया । मौके पर अवैध खनन का नाप किया आगे जिसके अनुसार इन दोनों पीटो से कुल 4.24 लाख टन बजरी का अवैध खनन हुआ जिसपर कुल रूपए 19.11 करोड़ की पेनल्टी तय की गई है। तहसीलदार कोलायत दोनों खातेदारी भूमियों को आराजीराज करेंगे।

‘पुलिस की वर्दी एक कपड़ा नहीं, जीवन का अर्थ है’

■ मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मैस भत्ता व वर्दी भत्ता बढ़ाने की घोषणा की तथा सेमी डीलक्स बसों में भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की।

■ भजनलाल शर्मा ने कहा कि पुलिस और नागरिकों के बीच नियमित संवाद से आमजन में विश्वास के साथ अपराध पर प्रभावी नियंत्रण होता है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस स्थापना दिवस पर आरसीए में परेड का निरीक्षण किया



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर परेड निरीक्षण के बाद समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस अधिकारी एवं कार्मिकों को पुलिस पदक तथा मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक दिये ।

माल की सुरक्षा करते हैं। शर्मा बुधवार को राजस्थान पुलिस अकैडमी (आर.पी.ए.) में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर परेड निरीक्षण के बाद

समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज का दिन प्रदेश के बहादुर पुलिसकर्मियों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है।

मुख्यमंत्री ने कर्तव्य पथ पर अडिग रहते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर

कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक तक के वर्दी भत्ते को 7 हजार रुपये से बढ़ाकर 8 हजार रुपये करने तथा पुलिस निरीक्षक तक के अधिकारियों का मैस भत्ता 2,400 रुपये से बढ़ाकर 2,700 रुपये करने की घोषणा की। शर्मा ने कांस्टेबल से पुलिस निरीक्षक तक के पुलिसकर्मियों को एक्सप्रेस श्रेणी की बसों के अलावा, सेमी डीलक्स बसों में भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा भी की। शर्मा ने कहा कि पुलिस और समाज एक-दूसरे के पूरक है। पुलिस और नागरिकों के बीच नियमित संवाद से आमजन में विश्वास के साथ अपराध पर प्रभावी नियंत्रण होता है। उन्होंने कहा, सामुदायिक पुलिसिंग के तहत गांवों-मोहल्लों में बैठकें आयोजित की जानी चाहिए, जिससे लोगों को पुलिस के कार्यों को समझने में मदद मिल सके।

मुख्यमंत्री ने पुलिस शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर वीर शहीदों को नमन किया। इसके बाद उन्होंने परेड ग्राउंड में परेड निरीक्षण किया। समारोह में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों को पुलिस पदक तथा मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए गए।

पुलिस महानिदेशक यू आर साहू ने बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर बजट में की गई घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।

अमेरिकी जज ने भारतीय छात्र का निर्वासन रोका

वाशिंगटन, 16 अप्रैल। अमेरिका की एक अदालत ने ट्रम्प प्रशासन को एक भारतीय स्नातक छात्र को निर्वासित करने से रोक दिया है, जिसका स्टूडेंट वीजा उसके स्नातक होने से कुछ ही हफ्ते पहले चार अप्रैल को रद्द कर दिया गया था। मैडिसन अदालत के डिस्ट्रिक्ट जज विलियम कॉर्नले ने कहा कि यूडब्ल्यू-मैडिसन के अंतर्राष्ट्रीय छात्र 21 वर्षीय कृष्ण लाल इस्सरदासानी का छात्र वीजा रद्द नहीं किया जा सकता और ट्रम्प प्रशासन उसके खिलाफ निर्वासन सहित कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। ट्रम्प प्रशासन द्वारा निर्वासन पर अस्थायी रोक लगाने का अनुरोध मैडिसन के वकील शबनम लोतफी द्वारा किया गया था, जब सरकार के छात्र एवं विनिमय आर्गुतुक कार्यक्रम (एसईवीआईएस) डेटाबेस में इस्सरदासानी का रिकॉर्ड समाप्त कर दिया गया था।

नाबालिग से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) आ गए। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

‘अन्नाद्रमुक चुनाव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) सरकार अन्नाद्रमुक ही बनायेगी।

अब, इडापडुडी के इस बयान के बाद, भाजपा की वे सारी योजनाएं उलट-पुलट हो जायेंगी, जो उसने तमिलनाडु को लेकर बनाई थीं। भाजपा तमिलनाडु में प्रवेश करने तथा वहाँ अपनी जड़ें जमाने के लिये पिछले कई वर्षों से जी-तोड़ कोशिश कर रही है। दरअसल, अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुये, भाजपा ने, अन्नाद्रमुक को खुश करने के लिये तथा विधानसभा चुनावों के लिये उसे एनडीए के घेरे में लेने के लिये, अपने नेता, के. अन्नामलाई को भी दरकिनार कर दिया था।

अन्नाद्रमुक महासचिव पलानीस्वामी ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि यह गठबंधन तो केवल चुनावों के लिये है। अन्नाद्रमुक सुप्रीमो का यह रूख ऐसे समय में सामने आया है जब पार्टी के अंदर भाजपा के साथ हुये गठबंधन को लेकर असंतोष बढ़ रहा है। खासकर, संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के पास होने के बाद कुछ पार्टी नेताओं के इस्तीफे भी आए हैं।

पार्टी सूत्रों ने कहा कि कुछ प्रभावशाली अल्पसंख्यक नेता या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या छोड़ने वाले हैं। भाजपा ने अन्नाद्रमुक प्रमुख के बयान पर अभी तक को कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन यह बात पक्की है कि वह इस बयान से खुश नहीं होगी। जब अन्नाद्रमुक, भाजपा के नेतृत्व वाले

एनडीए में शामिल हुई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गठबंधन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुये “एक्स” पर पोस्ट डाली थी, “मिलकर और भी मजबूत।”

गठजोड़ की घोषणा करते हुये, केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि दोनों पार्टियाँ मिलकर चुनाव लड़ेंगी तथा यह भी कहा था कि अन्नाद्रमुक ने कोई शर्त नहीं रखी है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा था, “हमने तय किया है कि अन्नाद्रमुक, भाजपा तथा गठबंधन की अन्य सभी विधानसभा चुनाव एनडीए के बैनर तले मिलकर लड़ेंगी।”

अन्नाद्रमुक भी, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक तथा भाजपा के साथ हुये गठजोड़ के परिणामस्वरूप, अल्पसंख्यक वोट के नुकसान के कारण, आशंकित एवं भयभीत हो रही है।

पिछले कुछ वर्षों में, जब-जब अन्नाद्रमुक ने भाजपा के साथ गठबंधन किया है, उसका प्रदर्शन खराब ही रहा है। 2021 का चुनाव अन्नाद्रमुक ने भाजपा के साथ मिलकर लड़ा था तथा केवल 75 सीटें जीत सकी थी, जबकि उससे पहले के चुनाव में उसे 136 सीटें मिली थीं इस प्रकार उसने सत्ता खो दी थी। 2019 तथा 2024 के लोकसभा चुनावों में अन्नाद्रमुक का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा था। 2024 के लोकसभा चुनावों में, वह राज्य की कुल 39 सीटों में से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी।

दादी के सामने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) लौट रहे थे। अचानक बाधिन ने झाड़ियों से बाहर आकर बच्चे पर हमला कर दिया। बाधिन ने बच्चे की गर्दन को मुंह में दबाया और पहाड़ियों की तरफ ओझल हो गई।

प्रत्यक्ष घटना को देखकर दादी वहां जोर-जोर से रोने लगी और बेसुध हो गई। लोगों ने तुरंत ही इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही डीएफओ और वनकर्मियों की टीम जंगल की ओर दौड़ पड़ी।

वनविभाग ने कैमरों से जांच करवाई तो बाधिन सुल्ताना झाड़ियों के बीच बच्चे के ऊपर पंजा रखकर बैठी नजर आई। वन विभाग के अधिकारी बाधिन से बच्चे को छुड़वाने के लिए मौके पर पहुंचे और काफी प्रयास किए। इसके बाद वन विभाग ने पटाखों का उपयोग कर बाधिन को वहां से हटाया। तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। वनविभाग ने देर शाम 4 बजकर 50 मिनट पर शव को बरामद किया।

(प्रथम पृष्ठ का शेष) स्टोर्स के दामों से अक्सर बहुत कम होते हैं, सौ की चीज दस में बेचते हैं।

यह रणनीति विशेष रूप से हानिकारक इसलिए है, क्योंकि सप्लायर लागत की बारीकी में जाकर, जिन सुपर लग्जरी बैग्स की खुदरा कीमत, उदाहरण के लिए, 34,000 डॉलर (करीब 29 लाख) हैं, उन्हें कथित रूप से केवल 1400 डॉलर में बना रहे हैं। इस खुलासे ने सोशल मीडिया में खलबली मचा दी है। लग्जरी रीटेल के मूल्य निर्धारण में बरती जाने वाली “नैतिकता” को लेकर बातें शुरू हो गई हैं तथा यह बात भी उजागर हुई है कि उपभोक्ता आमतौर पर लग्जरी गुड्स पर कितना भारी प्रीमियम देते हैं। इन वायरल वीडियो ने तीव्र बहस छेड़ दी है, खासकर जब अमेरिका ने, वर्तमान में चीन से अमेरिका आने वाले सामान की एक विस्तृत श्रृंखला पर 145 प्रतिशत तक का टैरिफ लगाया

है। तथापि, चीनी सप्लायरों ने इन चुनौतियों से बचने का रास्ता ढूंढ लिया है, और साथ ही साथ वो अपने सामान को अभी भी अन्तर्राष्ट्रीय ग्राहकों तक पहुँचा रहे हैं। कई लोग लग्जरी आइटम्स को कम ड्यूटी वाली श्रेणियों में घोषित करते हैं, कभी –कभी तो उच्च-स्तरीय चमड़े के हैंडबैग को सीमा शुल्क कम करने के लिए एक साधारण ‘पीयू बैग’ या ‘उपहार वस्तु’ के रूप में लेबल करते हैं।

सप्लायरों ने एक और तरीका अपनाया है। पहले वो अपना सामान साउथईस्ट देशों को भेजते हैं, फिर माल को उन देशों के उत्पादों के रूप में पुनः निर्यात करके, अक्सर सबसे ऊँचे अमेरिकी टैरिफ से बच जाते हैं– एक गतिविधि, जिसे ट्रांसशिपमेंट के रूप में जाना जाता है। हालाँकि, अमेरिकी सीमा शुल्क अधिकारियों ने इसे रोकने के लिए जांच बढ़ा दी है, लेकिन अनौपचारिक व्यापार चैनलों में यह

प्रथा अभी भी बनी हुई है।

इसके अतिरिक्त, कई चीनी सप्लायरों ने आयात शुल्क स्वयं वहन करना शुरू कर दिया है। इन अतिरिक्त लागतों के बावजूद, उनके लिए लाभ कमाने के लिए पर्याप्त मार्जिन रहता है, क्योंकि उन्हें लग्जरी ब्रांडिंग, विज्ञापन ओवरहेड्स और खुदरा मार्कअप के लिए धन खर्च नहीं करना पड़ता। कुछ मामलों में, सामान को बल्क कॉमर्शियल शिपमेंट के बजाय, छोटी-छोटी व्यक्तिगत खेपों के रूप में भेजा जाता है, जिससे सीमा शुल्क जांच और टैरिफ देनदारियां कम हो जाती हैं।

कुछ सप्लायर हांगकांग, दुबई या सिंगापुर जैसे टैरिफ –अनुकूल या कर–मुक्त क्षेत्रों में अपने गोदाम रखते हैं। इन स्थानों से वो ऑर्डर पूरा करते हैं, कभी–कभी कम शुल्क ब्रेकेट तक पहुँचने या प्रतिबंधों को पूरी तरह से बाईपास करने के लिए अपने सामान को “नॉन चाइना ओरिजिन” (गैर चीन

मूल) का रूप दे देते हैं।

वायरल हुए क्लिप चीनी उत्पादों की क्वालिटी के बारे में लंबे समय से चली आ रही धारणाओं को भी तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग वीडियो में दिखा रहे हैं कि इन लग्जरी आइटम्स को बनाने में कितनी सावधानी बरती जाती है तथा कितनी कुशलता से इन्हें बनाया जाता है।

इसके अलावा, कितना हाई ग्रेड का रॉ मटीरियल उपयोग में लिया जाता है तथा इन्हें बनाने वाले कारीगर कितने अनुभवी हैं। ऐसा करके सप्लायर इस धारणा को भी चुनौती देना चाहते हैं कि चीन में निर्मित सामान स्वाभाविक रूप से हीन या घटिया होता है।

बीजिंग के लिए, यह जवाबी कार्रवाई उसकी व्यापक आर्थिक रणनीति के अनुरूप प्रतीत होती है। जबकि, अमेरिका दंडात्मक टैरिफ के साथ चीनी माल को लक्षित कर रहा है, चीन ने 125 प्रतिशत तक के शुल्क के

साथ जवाबी कार्रवाई की है और घरेलू सुधारों को गहरा करने और अपनी वैश्विक आर्थिक साझेदारी का विस्तार करने पर ध्यान केन्द्रित किया है। चीनी अधिकारियों ने वाशिंगटन के ट्रेड एक्शनस को एकतरफा “दादागिरी” बताया है और दबाव की रणनीति का विरोध करने का संकल्प लिया है।

यह नया घटनाक्रम इंगित करता है कि कैसे व्यापार युद्ध बोर्डरूम और टैरिफ शीट से आगे बढ़कर सार्वजनिक और डिजिटल क्षेत्रों में चला गया है, चीनी सप्लायर, बाजार में पश्चिमी लग्जरी ब्रांडों के प्रमुख को अस्थिर करने के लिए, उपभोक्ता से सीधे जुड़ाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा करके, वे न केवल लग्जरी मूल्य निर्धारण मॉडल के अंदरूनी कामकाज का खुलासा कर रहे हैं, बल्कि यह भी परीक्षण कर रहे हैं कि आर्थिक शत्रुता के माहौल में ग्रे-मार्केट कॉमर्स कितनी दूर तक फैल सकता है।

एकल पट्टा प्रकरण...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने बताया कि पूर्व में राज्य सरकार ने एसीबी कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर पूर्व आईएएस जीएस संघू सहित, अन्य के खिलाफ लंबित मुकदमे को वापस लेने की गुहार की थी, जिसे एसीबी कोर्ट ने खारिज कर दिया था। एसीबी कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में रिवीजन याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने दलील दी कि अभियोजन वापस लेने का पूर्व का निर्णय औचित्यहीन है और मौजूदा राज्य सरकार आरोपियों के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर केस को आगे बढ़ाना चाहती है। वहीं, राज्य सरकार को यह अधिकार है कि यदि जांच में कोई कमी, गलती है या जांच दोषपूर्ण है तो वह न्याय के लिए उस संबंध में पूर्व में लिए गए निर्णय पर

भी पुनर्विचार कर सकती है। इसलिए उन्हें रिवीजन याचिका वापस लेने की मंजूरी दी जाए इस दौरान आरोपी पक्ष की ओर से मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस आरएस राठौड़ की कमेटी के गठन पर भी सवाल उठाया गया।

गौरतलब है कि इस मामले में अदालत ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने वाले अशोक पाठक को हाईकोर्ट में पक्षकार बनाए जाने के मुद्दे पर भी फैसला सुरक्षित रख लिया था।

दरअसल राज्य सरकार ने इस मामले में प्रार्थना पत्र पेश कर कहा है कि एसीबी कोर्ट के समक्ष दायर क्लोजर रिपोर्ट अधूरी व दोषपूर्ण साक्ष्यों पर की गई जांच के आधार पर पेश हुई थी। इसके चलते ही पूर्व मंत्री शांति धारीवाल को राहत मिली थी।

इस बेमिसाल अवसर को हरगिज़ न गवाएं! जल्दी करें!

अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी एरीना कार पर जबर्दस्त ऑफ़र्स पाएं .

3 years

100 000 km WARRANTY**

EXTENDABLE UPTO 6 YEARS

विशेष ऑफ़र

ALTO K10 ₹68 100* | S-PRESSO ₹63 100*
WAGONR ₹68 100* | CELERIO ₹68 100*

SCAN TO CONNECT TO SHOWROOM NEAR YOU

E-BOOK TODAY AT WWW.MARUTISUZUKI.COM

Contact us at
1800-102-1800

T&C Apply Features and accessories shown may not be part of standard fitment. Black Glass Shade on the vehicle is due to the lighting effect. Images used are for illustration purposes only. Car color may vary due to printing on paper. Offers vary across variants. Maruti Suzuki India Limited reserves the right to discontinue offers without notice. *Offer includes consumer offer, exchange bonus and institutional or rural offer (wherever applicable) on selected models/variants. Above mentioned savings amount is the value of maximum savings on selected models. Offer valid with selected financiers only. **3 years or 100 000 km whichever is earlier. Above offers are valid till 30th April, 2025.

राष्ट्रदूत हिन्दू संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाइन्ट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, अय्यड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513 कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हथ्या, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चूंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908